



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बोरवार, 4 दिसम्बर, 2003/13 अग्रहायण, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

शिमला, 14 नवम्बर, 2003

संख्या पी० सी० एच०-एस० एम० एल० (त्याग-पत्र)/2003-16039.—यह कि श्री राजीव कुमार सुर्याण, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत रोहल, विकास खण्ड छोहारा, जिला शिमला की नियुक्ति ग्रामीण विद्या उपासक, राजकीय प्राथमिक पाठशाला, हिनगोरी में हुई है जिस कारण श्री राजीव कुमार सुर्याण, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत रोहल ने अपने पद से त्याग-पत्र दिया है तथा त्याग-पत्र को स्वीकृत करने हेतु लिखा है।

अतः मैं, जोगिन्द्र कुमार शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 (1) तथा हिमाचल प्रदेश (सामान्य) नियम 1997 के नियम 135 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राजीव कुमार, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत रोहल के त्याग-पत्र को स्वीकृत करता हूँ तथा उप-प्रधान पद ग्राम पंचायत रोहल को रिक्त घोषित करता हूँ।

जोगिन्द्र कुमार शर्मा,
जिला पंचायत अधिकारी,
शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

कार्यालय उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

शिमला-1, 20 नवम्बर, 2003

संख्या पी० सी० एच०-एस० एम० एल० (दो बच्चे)/2002-17026-33.—यह कि पंचायत निरीक्षक खण्ड विकास अधिकारी, चौपाल से प्राप्त सूचना अनुसार तथा ग्राम पंचायत खदर के पंचायत अभिलेख परिवार रजिस्टर, जन्म पंजीकरण रजिस्टर तथा राशन कार्ड रजिस्टर की जांच इस कार्यालय में उपायुक्त महोदय के द्वारा करवाने के उपरान्त पाया गया कि उपरोक्त रजिस्ट्रों में कटिंग तथा अन्य अनियमिततायें पाई गईं जिनसे उक्त प्रधान श्री गीता राम, ग्राम पंचायत खदर ने अपनी दूसरी जीवित सन्तान के होते हुए दिनांक 2-9-2001 को पांचवीं सन्तान पैदा करके हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ण) की उल्लंघना की है इस सम्बन्ध में उसे इस कार्यालय के पत्र संख्या पी० सी० एच०-एस० एम० एल० (दो बच्चे)/2002-13073-80, दिनांक 22-10-2003 के अन्तर्गत जारी नोटिस अनुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था।

यह कि उक्त श्री गीता राम, प्रधान, ग्राम पंचायत खदर को इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त नोटिस के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है जबकि विहित अवधि भी समाप्त हो चुकी है। इससे यह स्पष्ट है कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

यह कि पंचायत निरीक्षक खण्ड विकास अधिकारी, चौपाल की रिपोर्ट अनुसार उक्त श्री गीता राम, प्रधान, ग्राम पंचायत की पांचवीं सन्तान उत्पन्न हुई है। जिससे स्पष्ट होता है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) तथा हि० प्र० पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 19 द्वारा अन्तःस्थापित खण्ड (ण) की उल्लंघना करते हुए 8-6-2001 के पश्चात् अर्थात् 2-9-2001 को पांचवीं सन्तान पैदा करके वह उक्त ग्राम पंचायत के प्रधान पद पर बने रहने के लिये निरहित हो गये हैं।

अतः मैं, एम० के० बी० एस० नेगी, उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला, हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (2) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की संशोधित धारा 122 (1) (ण) की उल्लंघना करने पर श्री गीता राम, प्रधान, ग्राम पंचायत खदर को ग्राम पंचायत के प्रधान पद पर बने रहने के लिये अयोग्य घोषित करता हूँ तथा उक्त अधिनियम की धारा 131 (2) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खदर के प्रधान पद को रिक्त घोषित कर यह आदेश देता हूँ कि उसके पास ग्राम पंचायत की किसी भी प्रकार की कोई देनदारी हो तो उसे तुरन्त सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी अथवा पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत खदर को सौंप दे।

कारण बताओ नोटिस

शिमला-1, 21 नवम्बर, 2003

संख्या पी० सी० एच०-एस० एम० एल० (दो बच्चे)/2002-17035-39.—एतद्वारा श्रीमती कला देवी सदस्या, ग्राम पंचायत फांचा, वार्ड नं० 3 (कांचरी पशगांव), विकास खण्ड रामपुर, जिला शिमला (हि० प्र०) का ध्यान हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम की धारा 19 द्वारा अन्तःस्थापित खण्ड (ण) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो निम्नतः है:—

कोई व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए निरहित होगा, “यदि उसके दो, से अधिक जीवित सन्तान हैं, परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निरर्हता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसकी यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख पर य

ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के भीतर दो से अधिक जीवित सन्तान हैं, जब तक उसकी उक्त एक वर्ष की अवधि के पश्चात् और संतान नहीं होती"।

यह कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) 8 जून, 2001 से लागू हो चुका है तथा धारा 122 के खण्ड (ण) का प्रावधान भी 8 जून, 2001 से पूर्णतः प्रभावी होता है, अर्थात् 8 जून, 2001 अथवा इसके पश्चात् यदि किसी पंचायत पदाधिकारी की इस प्रावधान के लागू होने से पूर्व दो या दो से अधिक जीवित संतान है तथा उक्त प्रावधान के लागू होने के पश्चात् यदि कोई अतिरिक्त संतान उत्पन्न होती है तो वह पंचायती राज संस्था में पदासीन रहने के अयोग्य होगा।

यह कि ग्राम पंचायत एवं खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत फांचा की रिपोर्ट अनुसार उक्त श्रीमती कला देवी, सदस्य, वार्ड नं० 3, ग्राम पंचायत फांचा की 8-6-2001 तक दो जीवित संतान के होते हुए दिनांक 16-11-2002 को एक और संतान उत्पन्न हुई है, जिसका इन्द्राज जन्म पंजीकरण संख्या 188 में दर्ज है। जो कि पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (ण) के अन्तर्गत वर्णित अयोग्यता में आता है।

अतः मैं, एस०के० बी०एस० नेगी, उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, की धारा 122 (2) तथा 131 (2) के प्रावधान अनुसार उक्त श्रीमती कला देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत फांचा को निर्देश देता हूँ कि वह इस कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के उक्त प्रावधानों अनुसार ग्राम पंचायत फांचा के वार्ड नं० 3 से सदस्य पद को रिक्त घोषित कर दिया जाये। उनका उत्तर निर्धारित अवधि तक प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा तदोपरान्त उनके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

शिमला, 21 नवम्बर, 2003

संख्या पी० सी० एच०-एस० एम० एल० (4) 68/77-17040-45.—यह कि खण्ड विकास अधिकारी, छाँहारा से प्राप्त सूचना तथा ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी, पेखा की रिपोर्ट अनुसार श्री प्रशन लाल, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत पेखा, दिनांक 8-7-2003 से 17-10-2003 तक लगातार पंचायत की सात मासिक बैठकों में अनुपस्थित रहे हैं, जिस कारण पंचायत के विकास कार्यों तथा गणपूर्ति पूर्ण होने में बाधा उत्पन्न हो रही है। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह उप-प्रधान पद के कर्तव्यों को नियमानुसार निभाने में अपफल रहे हैं।

यह कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (ख) के अन्तर्गत पंचायत या इसकी समितियों की लगातार 3 बैठकों से अनुपस्थित रहा है या पंचायत की स्वीकृति के बिना 6 मास की कालावधि के दौरान की गई बैठकों की आधी संख्या में उपस्थित नहीं होता है तो वह उप-धारा 2 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये ऐसा पदाधिकारी नहीं रहेगा और उसका पद रिक्त हो जायेगा।

यह कि उक्त उप-प्रधान श्री प्रशन लाल, ग्राम पंचायत पेखा लगातार पंचायत की 7 मासिक बैठकों में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे हैं, जिस कारण उन्होंने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (ख) की उल्लंघना की है बल्कि ग्राम पंचायतों को गणपूर्ति तथा विकास कार्यों में भी बाधा उत्पन्न हुई है।

अतः मैं एस०के० बी०एस० नेगी, उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला, हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (ख) के प्रावधान अनुसार उक्त श्री प्रशन लाल, उप-प्रधान ग्राम पंचायत, पेखा को निर्देश देता हूँ कि वह इस कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना उत्तर

प्रस्तुत करें कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के उक्त प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत पेंखा के उप-प्रधान पद को रिक्त घोषित कर दिया जाये। उनका उत्तर निर्धारित अवधि तक प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है तदोपरान्त उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

शिमला, 21 नवम्बर, 2003

संख्या पी० सी० एच०-एस०एम०एल०(४)-४८/७७-१७०४६-५०.—यह कि ग्राम पंचायत बैश, विकास खण्ड वसन्तपुर, जिला शिमला के लेखों के अन्वेषण करते हुए यह पाया गया है कि श्रीमती उर्मिला, प्रधान, ग्राम पंचायत बैश द्वारा पंचायत क्षेत्र में बहुत से विकास कार्य करवाये गये हैं, परन्तु कार्य पूर्ण होने के उपरान्त भी सम्बन्धित मजदूरों/मिस्त्रियों को उनकी अदायगी नहीं की गई है तथा अपने पास अनाधिकृत रूप से नकद शेष राशि भी रखी है, जिसके कारण न केवल विकास कार्य प्रभावित हुये हैं बल्कि सभा निधि की भी हानि हुई है। यही नहीं उक्त प्रधान पंचायत बैठकों में उपस्थित हुई है और कार्यवाही करने के उपरान्त कार्यवाही रजिस्टर में कार्यवाही बन्द नहीं की गई है, जिस कारण जो कार्यवाही हुई है उन पर आगामी आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा सकी है। इस तरह वह अपने कार्य व कर्तव्यों को भली-भान्ति निभाने में विफल रही हैं। अनियमितताओं का विवरण निम्न प्रकार से दिया जा रहा है:—

1. यह कि ग्राम पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन से पाया गया है कि उक्त प्रधान श्रीमती उर्मिला के पास नकद शेष के रूप में रु० 9000.00 रुपये की राशि दिनांक 26-6-2003 से आज तक रखी गई है, जिसका समायोजन विभिन्न कार्यों पर जिसके लिये राशि निकाली गई थी नहीं किया गया है।
2. यह कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला, पनिहारा मैदान निर्माण हेतु रु० 20000.00 रुपये की राशि स्वीकृत हुई है पंचायत को इस कार्य के लिये 10000.00 रुपये की राशि अदा हो चुकी है तथा मौका पर कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसका मूल्यांकन 20325.00 रुपये आंका गया है इस कार्य की दूसरी किश्त रु० 10000.00 रुपये प्रधान द्वारा विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त नहीं की गई है और कार्य पर लगे मजदूरों/मिस्त्रियों को आज दिन तक उनकी मजदूरी की अदायगी नहीं की गई है।
3. यह कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला, करौडी मैदान के निर्माण कार्य के लिए रु० 10000.00 रुपये की स्वीकृति हुई है पंचायत को इस राशि में से रु० 5000.00 रुपये की पहली किश्त प्राप्त हो चुकी है और मौका पर कार्य भी पूर्ण हो चुका है, जिसका मूल्यांकन 10312.50 रुपये आंका गया है प्रधान द्वारा दूसरी किश्त रु० 5000.00 रुपये विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त नहीं की गई है और कार्य पर लगे मजदूरों/मिस्त्रियों को आज दिन तक उनकी मजदूरी की अदायगी नहीं की गई है।
4. यह कि चबुतरा निर्माण ग्राम टिक्कर घाटी कार्य के लिये रु० 25000.00 रुपये की स्वीकृति हुई है पंचायत को इस राशि में से रु० 10000.00 रुपये की पहली किश्त प्राप्त हो चुकी है और मौका पर कार्य भी पूर्ण हो चुका है। परन्तु प्रधान द्वारा दूसरी किश्त रु० 15000.00 रुपये प्रधान द्वारा विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त नहीं की गई है और कार्य पर लगे मजदूरों/मिस्त्रियों को आज दिन तक उनकी मजदूरी की अदायगी नहीं की गई है।
5. यह कि जे०जी०एस०वाई० मदद के अन्तर्गत निर्माण रास्ता रुंगी से ढगैणा हेतु रु० 10000.00 रुपये स्वीकृत हुये हैं तथा यह राशि पंचायत को अदा की जा चुकी है, जो पंचायत खाते में जमा है और मौका पर कार्य पूर्ण हो चुका है परन्तु कार्य पर लगे मजदूरों/मिस्त्रियों को आज दिन तक उनकी मजदूरी की अदायगी नहीं की गई है।
6. यह कि उपरोक्त अनुसार जे०जी०एस०वाई० नद् से निर्माण बावड़ी गांव तून हेतु रु० 14920.00 रुपये की स्वीकृति हुई है पंचायत को यह राशि अदा हो चुकी है, जो पंचायत खाते में जमा है और

मौका पर कार्य पूर्ण हो चुका है परन्तु कार्य पर लगे मजदूरों/मिस्त्रियों को आज दिन तक उनकी मजदूरी की अदायगी नहीं की गई है।

7. यह कि दिनांक 8-10-2003 को पंचायत बैठक के लिए जो एजेंडा रखा गया था उस पर विचार-विमर्श हुआ। इस बैठक में प्रधान श्रीमती उर्मिला उपस्थित हुई परन्तु बैठक में चर्चा उपरान्त कार्यवाही बन्द करने पर उक्त प्रधान ने कार्यवाही रजिस्टर में हस्ताक्षर नहीं किये, जिस कारण उपरोक्त हुई कार्यवाही पर कोई आगामी कार्यवाही नहीं की जा सकी, जिसके कारण न तो राशि बैंक से निकाली जा सकी तथा न ही पूर्ण हुये कार्यों की सम्बन्धित मजदूरों/मिस्त्रियों की अदायगी की जा सकी।
8. यह कि उक्त प्रधान दिनांक 29-3-2003 के उपरान्त कभी भी खण्ड विकास कार्यालय, बसन्तपुर नहीं गई, जिसके कारण निर्माण कार्यों की दूसरी व अन्तिम किश्त पंचायत को प्राप्त नहीं हुई है, जिसके फलस्वरूप सम्बन्धित मजदूर व मिस्त्री बिना अदायगी के कठिनाई का सामना कर रहे हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि श्रीमती उर्मिला, प्रधान अपने कार्यों व कर्तव्यों को भली-भाँति निभाने में विफल रही हैं और नियमानुसार कार्य न करने से केवल विकास कार्य प्रभावित हुये हैं बल्कि मजदूर व मिस्त्री भी अपनी मजदूरी न मिलने के कारण परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

अतः मैं एस० के० बी० एस० नेगी, उपायुक्त, शिमला उन शक्तियों के अधीन जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा, 145(2) पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के अधीन प्राप्त हैं श्रीमती उर्मिला, प्रधान, ग्राम पंचायत बैंग, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला को यह कारण बताओ नोटिस जारी करता हूँ कि वह उक्त नोटिस का उत्तर 15 दिनों के भीतर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें अन्यथा विहित नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

शिमला-1, 21 नवम्बर, 2003

संख्या पी० सी० एच० एस० एम० एल० (4) 68/77-17051-56.—यह कि खण्ड विकास अधिकारी, रामपुर से प्राप्त सूचना तथा प्रधान, ग्राम पंचायत मुनिश-बाहली की रिपोर्ट अनुसार श्री पदम दास, सदस्य, ग्राम पंचायत मुनिश-बाहली, दिनांक 22-8-2001 से 22-3-2002 तक लगातार ग्राम पंचायत की 15 मासिक बैठकों में अनुपस्थित रहे हैं, जिस कारण पंचायत के विकास कार्यों तथा गणपूर्ति पूर्ण होने में बाधा उत्पन्न हो रही है। जिससे प्रतीत होता है कि वह सदस्य पद के कर्तव्यों को नियमानुसार निभाने में असफल रहे हैं।

यह कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (ख) के अन्तर्गत पंचायत या इसकी समितियों की लगातार 3 बैठकों से अनुपस्थित रहता है या पंचायत की स्वीकृति के बिना 6 मास की कालावधि के दौरान की गई बैठकों की आधी संख्या में उपस्थित नहीं होता है तो वह उप-धारा 2 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसा पदाधिकारी नहीं रहेगा और उसका पद रिक्त हो जायेगा।

यह कि उक्त श्री पदम दास, सदस्य, ग्राम पंचायत मुनिश-बाहली, दिनांक 22-8-2001 से 22-3-2002 तक लगातार पंचायत की 15 मासिक बैठकों में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे हैं, जिस कारण उन्होंने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (ख) की उल्लंघना की है बल्कि ग्राम पंचायतों को गणपूर्ति तथा विकास कार्यों में भी बाधा उत्पन्न हुई है।

अतः मैं, एस० के० बी० एस० नेगी, उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला, हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (ख) के प्रावधान अनुसार उक्त श्री पदम दास, सदस्य, ग्राम पंचायत मुनिश-बाहली को निर्देश देता हूँ कि वह इस कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के उक्त प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत, मुनिश-बाहली के सदस्य पद को रिक्त घोषित कर दिया जाये। उनका उत्तर निर्धारित अवधि तक प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है तदोपरान्त उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

कार्यालय आदेश

शिमला-171001, 27 नवम्बर, 2003

संख्या पी0सी0एच0-एस0एम0एल0 (4) 68/77-17120-26.—यह कि प्रधान/पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत धार-कन्दरू की रिपोर्ट अनुसार श्रीमती तोतू देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत धार-कन्दरू दिनांक 26-11-2002 से 5-10-2003 तक लगातार पंचायत की मासिक बैठकों से अनुपस्थित रही है इस तथ्य की पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी, ठियोग से कार्रवाई गई। पंचायत की कार्रवाई बुस्तिका की छानबीन से पाया गया कि उक्त श्रीमती तोतू देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत, धार-कन्दरू उपरोक्त वर्णित दिनांकों को पंचायत की बैठकों से लगातार अनुपस्थित रही है। जिस कारण वह पंचायत सदस्या पद के कर्तव्यों को नियमानुसार निभाने में असफल रही है।

यह कि इस बारे में अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्रीमती तोतू देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत धार-कन्दरू, विकास खण्ड ठियोग को कारण बताओ नोटिस संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0 (4) 68/77-13049, दिनांक 20-10-2003 को इस कार्यालय द्वारा जारी किया गया था जिसमें 15 दिन के भीतर-भीतर पंचायत बैठकों से अनुपस्थित रहने हेतु कारण स्पष्ट करने का समय दिया था। श्रीमती तोतू देवी से कारण बताओ नोटिस का जो उत्तर खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जो कि सन्तोषजनक नहीं पाया गया है क्योंकि वह दिनांक 26-11-2002 से 5-10-2003 तक निरन्तर पंचायत बैठकों से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रही है, जिससे यह स्पष्ट है कि उसकी पंचायत के कार्यों में कोई रुची नहीं रह गई है, जबकि उसे इस कार्यालय के सम संख्यक ज्ञापन दिनांक 2-9-2003 के अन्तर्गत नियमित रूप से बैठकों में भाग लेने हेतु परामर्श दिया गया था परन्तु बावजूद इसके ग्राम पंचायत की बैठकों से अनुपस्थित रही हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि श्रीमती तोतू देवी ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1) (ख) की उल्लंघना की है तथा वह ग्राम पंचायत धार-कन्दरू के सदस्य पद पर बने रहने के अयोग्य हो गई है।

अतः मैं एस0 के0 बी0 एस0 नेगी, उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(2) के अधीन प्राप्त है, श्रीमती तोतू देवी को सदस्या, ग्राम पंचायत धार-कन्दरू, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला के सदस्य पद को रिक्त घोषित कर, यह आदेश देता हूँ कि उसके पास ग्राम पंचायत की किसी भी प्रकार की कोई देनदारी हो तो उसे तुरन्त सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी/पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत धार-कन्दरू को सौंप दें।

एस0 के0 बी0 एस0 नेगी,
उपायुक्त,
शिमला, जिला शिमला (दि0 प्र0)।